दैनिक भास्कर
जयपुर • रविवार 29 अप्रैल 2012 • 2

अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान सोमवार से

1500 से अधिक अस्थायी अतिक्रमण, पुनर्वास की योजना नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

हटाने को 3 टीमें, बसाने के लिए कोई नहीं!

नगर संवाददाता. जयपुर

नगर निगम ने सोमवार से शहर में अतिक्रमण हटाने के अभियान शुरू करने की तैयारी तो कर ली है लेकिन बाजारों से हटाए जाने वाले फुटकर व्यापारियों को बसाया कहां जाएगा, इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं की। ऐसे में अभियान की सफलता पर शुरू होने से पहले ही फेल होने की आशंका मंडरा रही है।

वहीं शहर के व्यापारियों और थड़ी ठेले वालों ने चेतावनी दी है कि निगम अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेगा तो आंदोलन हो सकता है। इनकी मांग है कि पहले सुनियोजित प्लानिंग करके पुनर्वास की व्यवस्था हो, फिर अभियान शुरू किया जाए। साथ ही बरसों पहले हटाए गए लोगों को भी उचित जगह दी जाए ताकि उनकी रोजी रोटी की स्थाई व्यवस्था हो सके। शहर में विभिन्न बाजारों में करीब डेढ़ हजार लोगों ने वर्तमान में अस्थाई अतिक्रमण कर रखा है।

चांदपोल बाजार में अतिक्रमण का ये बाजार

तीन टीमों का गठन

निगम ने सोमवार से चांदपोल से सूरजपोल गेट के बीच हो रहे अस्थाई अतिक्रमण एवं व्यवधान को हटाने के लिए तीन टीमों का गठन किया है। एक टीम चांदपोल से तो दूसरी टीम सूरजपोल गेट से अस्थाई अतिक्रमण हटाएगी। तीसरी टीम मॉनिटरिंग का काम करेगी।

निगम सीईओ लोकनाथ सोनी ने बताया कि हवामहल जोन (पश्चिम) की टीम चांदपोल से बड़ी चौपड़ और हवामहल जोन (पूर्व)की टीम सूरजपोल गेट से बड़ी चौपड़ तक अस्थाई अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। मुख्यालय आयुक्त अवधेश सिंह एवं आयुक्त अनिता मीणा के नेतृत्व में बनी टीम मॉनिटरिंग का काम करेगी। उनका कहना है कि निगम तो एम्पावर्ड कमेटी के निर्देश की पालना कर रहा है। पहले कमेटी ने चौड़ा रास्ता से अतिक्रमण हटाने का काम सौंपा था। अब प्रथम चरण में चांदपोल से सूरजपोल गेट से अतिक्रमण हटाने का काम सौंपा है। पुनर्वास के लिए फिलहाल प्लानिंग नहीं की गई है, हम जल्द ही जगह चिह्नित कर लेंगे।

डेढ़ साल से नहीं हुआ पुनर्वास

▪ डेढ़ साल पहले रामगंज, बड़ी चौपड़ और घाटगेट बाजार से अस्थाई अतिक्रमण हटाए थे. उस समय निगम ने थड़ी ठेले वालों को सूरजपोल बाजार की छपा कर पुनर्वास करने की बात कही थी, लेकिन

पुनर्वास से पहले अतिक्रमण हटाया तो विरोध किया जाएगा।

-अजय यादव, पार्षद

पुनर्वास के लिए आवंटित कियोस्क नहीं खुले।

कियोस्क बने, खुले नहीं...अब टूट रहे हैं।

नगर निगम पहले बाजारों में सुविधाएं तो उपलब्ध कराए

▪ व्यापारी भी चाहते हैं कि बाजारों से अस्थाई अतिक्रमण हटाए जाएं, लेकिन निगम को इसके बाद बाजार को आदर्श बनाने की प्लानिंग करनी चाहिए। वर्तमान में घाटगेट

बाजार में शौचालय और प्याऊ तक की व्यवस्था नहीं है। अतिक्रमण हटाते समय भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अतिक्रमण हटने के बाद फिर से अतिक्रमण नहीं हो।

-दिनेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, घाटगेट बाजार

पहले जिनको हटाया, उनका ही नहीं हुआ पुनर्वास

चूड़ी वालों के खंदे से हटाए गए फुटकर व्यवसायियों का डेढ़ साल में भी पुनर्वास नहीं हुआ है। ऑपरेशन परकोटा के तहत हटाए गए ये व्यापारी आज भी नगर निगम अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं।

बड़ी चौपड़ से हटाए गए सर्राफे वाले फिर से बाईजी के खंदे में जम गए हैं वहीं त्रिपोलिया बाजार के गोखों से हटाए गए 17 फुटकर व्यापारियों में से छह ने पुरानी जगहों पर वापस व्यवसाय शुरू कर दिया है। शेष 11 लोग आज भी दर-दर भटक रहे हैं।

बिना प्लानिंग कार्रवाई हुई तो दस्ते को नहीं घुसने देंगे

▪ अभियान चलाने से पहले पुनर्वास की प्लानिंग बननी चाहिए। यदि रोजीरोटी की स्थाई व्यवस्था हो जाएगी तो स्वतः ही अतिक्रमण हट जाएंगे। अतिक्रमण हटाते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे थड़ी ठेले वालों का भी नुकसान नहीं होगा। पुनर्वास की प्लानिंग के बिना चांदपोल बाजार में कार्रवाई हुई तो निगम दस्ते को घुसने नहीं दिया जाएगा। - कैलाश चंद महावर, पार्षद

भेदभाव के बिना हटाए जाएं बाजारों से अतिक्रमण

▪ व्यापारी निगम की कार्रवाई का स्वागत करते हैं, लेकिन कार्रवाई में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण हटाने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। -सुभाष गोयल, महामंत्री, चांदपोल बाजार

12 साल में 11वें अभियान की तैयारी, व्यापारियों-जनप्रतिनिधियों के भारी विरोध की आशंका

10 बजे : बड़ी चौपड़ से हटेंगे अतिक्रमण

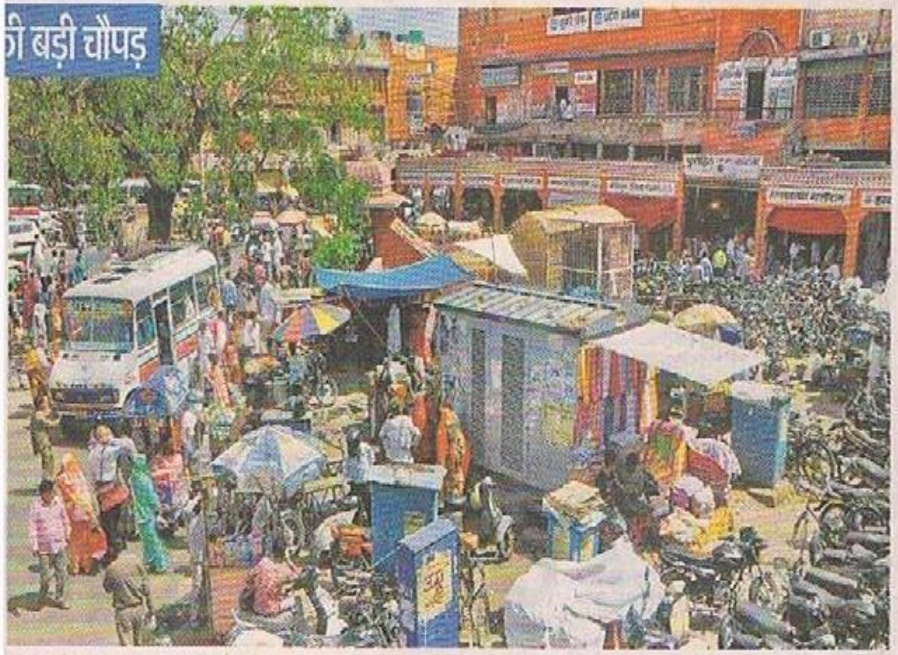

मार्च 2000 में ऑपरेशन पिंक से लेकर अब तक अतिक्रमण हटाने के लिए 11 अभियान चलाए जा चुके हैं, मगर मॉनिटरिंग की कमी से हर बार नतीजा सिफर हो जाता है। एक बार फिर निगम ने तैयारी की है। व्यापारी भी तैयार हैं, मगर शर्त...कार्रवाई निष्पक्ष हो और पुनर्वास की भी व्यवस्था हो।

नगर संवाददाता | जयपुर

शहर के बाजारों से अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार से निगम अभियान शुरू होगा। प्रथम चरण में निगम चांदपोल से सूरजपोल के बीच अतिक्रमण हटाएगा। दूसरे चरण में अन्य बाजारों में समझाइश के बाद हटाए जाएंगे। इसके लिए निगम ने

स्थायी पुनर्वास की मांग उठ गई है। बाजारों में फुटकर व्यवसाय करने वालों के साथ कई पार्षद और थड़ी-ठेला यूनियनों ने भी निगम प्रशासन से मांग की है कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था हो, फिर कार्रवाई हो।

चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच अस्थायी अतिक्रमण हटाने का जिम्मा

कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर : सीईओ

सोमवार से निगम शहर में हो रहे अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। यह निगम का अभियान नहीं है, बल्कि निगम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। निगम की कार्रवाई का अगर कोई विरोध करता है तो वह कोर्ट की अवमानना होगी। अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापारियों से बातचीत हो गई है। जनता

पहले रामगंज से हटें अतिक्रमण

अगर निगम पहले रामगंज और घाटगेट बाजार से अस्थायी अतिक्रमण हटाए। फिर अन्य बाजारों में कार्रवाई करे। कार्रवाई के पहले फुटपाथी व्यापारियों का पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए। रामगंज और घाटगे

कोतवाली पुलिस ने कर रखा है अतिक्रमण

एसीपी कहते हैं- अतिक्रमण नहीं किया, सीईओ को पता ही नहीं...

कोतवाली सर्किल के एसीपी नरपत सिंह का कहना है कि थाने के बाहर अतिक्रमण नहीं है। एक तरफ रेलिंग बनी हुई है। दूसरी तरफ

DNA
DAILY NEWS AND ANALYSIS

JMC TRIED TO REASON WITH TRADERS ON THE NEED TO REMOVE ENCROACHMENTS

Bulldozers back in Walled City

DNA Correspondent

On day one of the Jaipur Municipal Corporation's (JMC) drive against encroachment on Monday, civic officials tried to convince traders and local residents to help them work towards regaining lost glory of Walled City.

The campaign was initiated on the directives of the Supreme Court-constituted empowered committee to remove the encroachment in Walled City. The agitating traders and residents demanded the officials to rehabilitate people removed almost a year ago during Operation Parkota by the JMC.

DNA SCAN

BJP leaders gheraoed JMC CEO Loknath Soni at Badi Chaupar and demanded the rehabilitation of people removed during the Operation Parkota in 2011, said an official.

Municipal chief Soni said that the traders and residents of Walled City appreciated the campaign. However, the street vendors demanded their rehabilitation before removal.

The JMC has assured the vendors that they will be identified and treated according to the street vendor policy, said Soni.

He said that the campaign was started from Surajpole to Ramganj and Badi Chaupar, and traders had encroached upon the verandah in front of the shops and roads but they removed it without any resistance when asked to do so.

However, sources said that the residents at Ramganj agitated and raised slogans protesting against the campaign. When the encroachment wing reached Surajpole around 10.25 am, most street vendors who had encroached upon the road ran away with the goods. Interestingly, when the wing officials left the place, the vendors returned.

The JMC officials requested and convinced the traders to cooperate with them in the civic body's campaign against encroachment. They will once again try to remove the encroachers on Tuesday.

–Suman Sarkar, DNA

ON PEACEFUL NOTE: Anti-encroachment team with JMC CEO Loknath Soni asks a tailor to shift his sewing machine at Ramganj Bazaar (L) while a man dismantles his oven at Eda Ki Mohari, on Monday

NITTY-GRITTY

- The campaign was started from Surajpole to Ramganj and Badi Chaupar
- The residents at Ramganj agitated and raised slogans protesting against the campaign
- Most vendors encroaching upon roads in Surajpole ran away with their goods

Rehabilitation dents JMC drive

DNA Correspondent

The Jaipur Municipal Corporation (JMC) has again initiated a drive against encroachment in Walled City. But, it is running with political and administrative loopholes that busted the campaigns launched earlier.

'Rehabilitation' has emerged as a major administrative shortcoming which might fail the initiative as the civic officials have not planned on how and where to rehabilitate the affected people. The administration is promising a 'legal' employment under the state vendor policy. But, the policy is far from the implementation. Interestingly, the officials have not learnt lessons from the past and are trying to avoid these issues.

A year back, JMC had run 'Operation Parkota' and the affected were promised rehabilitation. Shockingly, the people could not be rehabilitated and returned to old places. If the drive meets the same fate, then there is no point in launching a drive. Deputy mayor Manish Pareek, too, blames poor rehabilitation plan for campaign's failure. "In Operation Parkota, the rehabilitation of affected people was planned, but it has not been executed. So, the drive will fail as they will be back again," said Pareek. The need of monitoring has been always felt after running an anti-encroachment drive. Involvement of municipal officials, police, traders and a councillor of Walled City could be a solution to maintain the impression of the drive. But, the civic body has never done it.

Gulam Nabi Azaad, chairman, anti-encroachment committee, hopes to make the drive a success. "The Supreme Court has ordered strict action. So, we can expect a fruitful drive. Role of police is also important as a proper monitoring could not be done. They should be serious this time."

A scooter parked inside a verandah in Ramganj – DNA